भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 423
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

नई राष्ट्रीय इस्पात नीति

423. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में इस्पात उत्पादन, खपत और निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या भारत हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है और यदि हां, तो क्या नई "राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017" को तद्नुसार अद्यतन किया जा रहा है;
(ग) क्या सरकार हरित इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकी अपनाने पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों में इस्पात उद्योग को बढ़ाने, रोज़गार उत्पन्न करने और एमएसएमई यूनिट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) वर्ष 2025-26 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान देश में उत्पादन, खपत और निर्यात से संबंधित डेटा नीचे दिया गया है :

वर्ष	**कच्चा इस्पात**	**तैयार इस्पात**		
	उत्पादन (एमटी)	**उत्पादन (एमटी)**	**खपत (एमटी)**	**निर्यात (एमटी)**
अप्रैल 2025-अक्टूबर 2025*	95.65	91.59	92.21	3.45
स्रोत: जेपीसी; एमटी = मिलियन टन*, अनंतिम				

(ख) से (ङ): विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्ष 2018 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना और तब से इस स्थान को बनाए रखा है। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्य शामिल हैं। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, इस्पात संयंत्र की स्थापना आदि से संबंधित निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 को सरकार और इस्पात क्षेत्र को एक प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता हो। हालाँकि, समय के साथ कुछ नई परिस्थितियों के कारण इस नीति में संशोधन की आवश्यकता हुई, जैसे- अकार्बनीकरण का बढ़ता महत्व, उन्नत तकनीकों को अपनाना, और विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की ज़रूरत। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए एक पायलट परियोजना लागू कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत अब तक इस्पात क्षेत्र में चार पायलट परियोजनाएँ प्रदान की जा चुकी हैं।

****